to Madhya Pradesh Government during the current year for providing drinking water facility to that state; and.

(b) the areas and number of persons likely to be benefited by the central assistance?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JANARDHAN POOJARI (a) under the Centrally Sponsored Accelerated Rural water Supply Programme (ARWSP), a sum of Rs. 2773 crores is likely to be given as Central assisance in 1988-89 for providing drinking water facilities in ural areas. Out of this, a sum of Rs 13.876 crores has already been released as first instalment of funds For Mini-Mission project areas taken up under the National Drinking Water Mission in the State a sum of Rs. 0 50 crore has been released in 1988-89. The allocation of the State Government for water cnservatin schemes to be funded out of Rural Landless Employees Guarantee Programme (RLEGP os Rs. 1.38 crores, Release of further assistance will depend upon physical an financial progress of the schemes and fulfilment of prescribed conditions.

(b) As per the action plan for 1988-89, with the above assistance, 2500 problem villages will be severed fully and 2800 problem villages partially with safe drinking water faciities. The popuation to be benefitted is 30.62 lakhs including 4.32 lakh S.C. and 6.24 lakh of S.T. population.

Release of grant for slum clearance in Bombay

331. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

((a) whether any amount has actually been given to the Government of Maharashtra out of Rs 100 crore grant specially sanctioned by the Prime Minister for slum clearance in Bombay;

(b) if so, what was he amount granted; and

(c) by when the balance of the amount is likely to be given?

THE MINISER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH). (a) and (b) Out of the Special Grant of Rs. 100 crores to the Government of Maharashtra for solving the acuter problems of housing and slums in Bombay Rs 30 crores have already been released to the State Government.

(c) Depending upon progress of implementation, it is proposed to release the balance grants during the current plan period itself

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का विस्तार

332. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की राज्यवार विस्तार योजनाएं क्या क्या हैं;

(ख) टी. वी. अपलिंकिंग ट्रांसमीटरों तथा माइक्रोवेव लिंकिंग के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इनसे कितने राज्य लाभान्वित हैं तथा अन्य राज्यों को ये सुविधाएं कब तक प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में अहमदाबाद-गुजरात के लिये प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आकाशवाणी—

सातवीं योजना (1985–86) के दौरान आकाशवाणी की विस्तार योजनाओं को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण I में विवरण–4 में दिए गए हैं [देखिये परिशिष्ट CXVIII, अनुषंग सं० 15]

सातवीं योजना (1985–90) के दौरान दूरदर्शन की विस्तार योजनाओं

को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण 5 और 6 में दिए गए हैं। ([देखिये परिशिष्ट CXVIII अनुबंध संख्या 15]

(ख) आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रादेशिक सेवा का उपग्रह आधारित टेलीकास्ट पहले ही शुरू हो गया है। तमिलनाडु में भी इसी प्रकार की सीमित सेवा शीघ्र ही शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक उड़ीसा और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को इन्सेट-सी के चालू हो जाने अर्थात्‌ सुविधाओं की उपलब्धता पर उपग्रह आधारित प्रादेशिक सेवा प्राप्त करने के लिए चुना गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाड् और पंजाब में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर माइक्रोवेव लिंको के जरिए संबंधित कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों से जुड़े हुए हैं। कोवीन और कालीकट के टी.वी. ट्रांसमीटरों के वर्ष 1988-89 के दौरान माइक्रोवेव के जरिए दूरदर्शन केन्द्र त्रिवेन्द्रम से जोड़ दिए जाने की उम्मीद है।

(ग) यदि अतिरिक्त ट्रांसपोंडर इन्सेट 1-सी में उपलब्ध हो जाएं तो 1990 के दशक के प्रारंभ में अथवा इससे पहले इन्सेट-2 के चालू हो जाने के फलस्वरूप गुजरात में सभी टी. वी. ट्रांसमीटरों के दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद से जोड़ दिए जाने की परिकल्पना है।

पड़ोसी देशों द्वारा सांस्कृतिक आक्रमण

333. **श्री मीर्जा इर्शादबेग:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को कुछ पड़ोसी देशों द्वारा अपने दूरदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक आक्रमण किये जाने के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) क्या देश के सीमावर्ती राज्यों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध कराते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाता है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) और (ख) देश के कुछ सीमा क्षेत्रों में विदेशी टेलीविजन सिग्नल प्राप्त होने की सरकार को जानकारी है। अत: सातवीं योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में टेलीविजन सेवा की किए जाने पर विशेष बल दिया गया है इस प्रयोजन के लिए तैयार की गयी विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वित होने पर देश पर सीमावर्ती जिलों की लगभग 86 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन द्वारा कवर किए जाने की संभावना है।

कपास का उत्पादन

334. **श्री मीर्जा ईर्शादबेग:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कपास का कितना उत्पादन हुआ और उसके लिये कपास उत्पादकों को प्रति क्विंटल कितना मूल्य प्राप्त हुआ;

(ख) देश को निजी आवश्यकता की अपेक्षा यह मात्रा कितनी कम या अधिक थी; और

(ग) क्या कपास उत्पादक संघ ने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) पिछले तीन वर्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के साथ कपास उत्पादन के अनुमान नीचे दिये गये है:-